

(To be published in Part IV of Delhi Gazette, Extraordinary)  
Government of National Capital Territory of Delhi,  
(Department of Law, Justice & Legislative Affairs),  
8th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate,  
New Delhi-110002.

No. F.14 (29) / LA-2001/903

Dated 2nd November, 2001

The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on the 2nd November, 2001 and is hereby published for general information :-

The Indian Stamp (Delhi Second Amendment ) Act, 2001  
(Delhi Act No.12 of 2001).

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 26th September, 2001).

AN  
ACT

Further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the National Capital Territory of Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows:-

**Short title, extent and commencement.**

- 1.(1) This Act may be called the Indian Stamp (Delhi Second Amendment) Act, 2001.
- (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (3) It shall be deemed to have come into force on the Thirty First day of July, 2001.

**Amendment of section 27.**

- 2.(1) In the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) as in force in the National Capital Territory of Delhi (hereinafter referred to as "the principal Act"), in section 27,-

- (a) in sub-section (1), after the words and brackets "the consideration (if any)", the words "and the market value" shall be inserted;
- (b) after sub-section(2), the following sub-section shall be inserted, namely:-



**Insertion of new section 47A.**

**"Instruments undervalued how to be dealt with.**

"(3) In the case of instruments relating to land, chargeable with ad valorem duty, the Government may notify minimum rates for valuation of land."

3. In the Principal Act, after section 47, the following section shall be inserted, namely:-

47A. (1) If the Registering Officer, while registering any instrument transferring any property, has reason to believe that the value of the property or the consideration, as the case may be, has not been truly set forth in the instrument, he may, after registering such instrument, refer the same to the Collector for determination of the value or consideration, as the case may be, and the proper duty payable thereon.

(2) On receipt of a reference under sub-section(1), the Collector shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and after holding an enquiry in such manner as may be prescribed by rules made under this Act, by order, determine the value of the property or the consideration and the duty aforesaid; and the deficient amount of duty, if any, shall be payable by the person liable to pay the duty and, on the payment of such duty, the Collector shall endorse a certificate of such payment on the instrument under his seal and signature.

(3) The Collector may, suo motu within two years from the date of registration of any instrument not already referred to him under sub-section (1), call for and examine the instrument for the purpose of satisfying himself as to the correctness of its value or consideration, as the case may be, and the duty payable thereon, and if after such examination, he has reason to believe that





the value or consideration has not been truly set forth in the instrument, he may determine the value or consideration and the duty aforesaid in accordance with the procedure provided for in sub-section (2), and the deficient amount of duty, if any, shall be payable the person liable to pay the duty and, on the payment of such duty, the Collector shall endorse a certificate of such payment on the instrument under his seal and signature.

(4) Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) or sub-section (3) may appeal to the District Court within whose jurisdiction the property transferred is situated.

(5) An appeal under sub-section (4) shall be filed within thirty days of the date of the order sought to be appealed against.

(6) The District Court shall hear and dispose of the appeal in such manner as may be prescribed by rules under this Act.

Explanation. - For the purpose of this section, value of any property shall be estimated to be the price which in the opinion of the Collector or the appellate authority, as the case may be, such property would have fetched, if sold in the open market on the date of execution of the instrument relating to the transfer of such property".



#### **Repeal and savings**

4.(1) The Indian Stamp (Delhi Second Amendment) Ordinance, 2001 (1 of 2001) is hereby repealed.

2 Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act.



(S.R. Maheshwari)  
Under Secretary (Law & Judicial)

S. R. MAHESHWARI  
Under Secretary (L.&J.)  
Govt. of Delhi.  
(Law & Judl. Deptt.)  
Delhi Sachivalaya,  
New Delhi.

॥दिल्ली राजपत्र आसाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ ॥  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,  
॥विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग॥,  
8वां तल, "सी" ब्लॉक, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002

संख्या:पा.14॥29॥विधायी कार्य/2001/903 दिनांक 2 नवम्बर, 2001

भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 2.11.2001 को मिली अनुमति के पश्चात्  
निम्न अधिनियम को जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

भारतीय मुद्रांक ॥दिल्ली द्वितीय संशोधन॥ अधिनियम, 2001

॥दिल्ली अधिनियम संख्या:12 वर्ष, 2001॥

॥राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2001 को  
यथा पारित ॥.

एक  
अधिनियम

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 का फिर से  
संशोधन करने के लिए तथा उनके प्रवर्तन के लिए

इसे भारतीय गणतंत्र के बावनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की  
विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएगा ।

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम को भारतीय  
मुद्रांक (दिल्ली द्वितीय  
संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जाएगा।

(2) यह समूची दिल्ली राष्ट्रीय  
राजधानी पर विस्तारित होता है ।

(3) यह 31 जुलाई, 2001 से प्रभावी  
होगा ।

धारा 27 का संशोधन

2. (1) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी  
में यथापूर्वत्त भारतीय मुद्रांक  
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) (इसके  
उपरांत मूल अधिनियम के रूप में  
संदर्भित ) की धारा 27 में ,

(क) उप-धारा (1) के उपरांत शब्द  
तथा कोष्ठक " प्रतिफल राशि (यदि  
कोई हो ) " के उपरांत शब्द "तथा  
बाजार मूल्य" शामिल किये जाएंगे,



(ख) उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा शामिल की जाएंगी, अर्थात् :-

3. भूमि संबंधी प्रलेखों की स्थिति में, मूल्यानुसार प्रभार्य, सरकार भूमि के लिए न्यूनतम दरें अधिसूचित कर सकती है ।

नई धारा 47 क का समावेशन

3. मूल अधिनियम में धारा 47 के उपरांत निम्नलिखित धारा शामिल की जाएगी, अर्थात् :-

“ न्यून मूल्यांकित प्रलेखों का कैसे निपटान किया जाए

47 क (1) किसी सम्पत्ति को स्थानान्तरित करने संबंधी किसी प्रलेख का पंजीकरण करते समय यदि किसी पंजीकरण अधिकारी के पास विश्वसनीय आधार हो कि सम्पत्ति का मूल्य या प्रतिफल राशि, जैसी भी स्थिति हो, प्रलेख में सही नहीं दर्शाई गई है, तो वह ऐसे प्रलेख को पंजीकृत करने के उपरांत इसे वह समाहर्ता के पास इसका मूल्य या प्रतिफल राशि, जैसी भी स्थिति हो, तथा इस पर देय उपयुक्त शुल्क को ज्ञात करने के लिए भेजेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अर्न्तगत किसी पत्र की प्राप्ति होने पर समाहर्ता पक्षकारों को सुनवाई का एक यथाचित अवसर देने के उपरांत तथा इस अधिनियम के अर्न्तगत बनाये गये नियमों द्वारा यथा निर्धारित पद्धति से एक जांच कराने के उपरांत सम्पत्ति कर मूल्य या प्रतिफल राशि तथा पूर्वोक्त शुल्क आदेश से ज्ञात करेगा, तथा यदि शुल्क की राशि में कुछ कमी हो, तो शुल्क के भुगतान के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा

देय होगी तथा ऐसे शुल्क के भुगतान करने पर समाहर्ता अपनी मोहर तथा हस्ताक्षरों से प्रलेख पर ऐसे भुगतान का एक प्रमाण पत्र अंकित करेगा ।

(3) समाहर्ता, किसी ऐसे प्रलेख को जिसका उल्लेख उप-धारा (1) में पहले नहीं किया गया है पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर अपनी तरफ से कार्यवाई करके मंगा सकता है तथा इसकी कीमत या बिकी मूल्य, जैसी भी स्थिति हो, इस पर देय शुल्क की सत्यता से स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से जांच कर सकता है तथा उक्त जांच के पश्चात् वह इस पर विश्वास करने के कारण जानता है कि विलेख में उल्लिखित मूल्य या बिकी राशि को पूरा नहीं किया गया है तो वह उप-धारा (2) में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार मूल्य या बिकी राशि तथा उक्त शुल्क का निर्धारण कर सकता है तथा ड्यूटी पर कम लगाई गई राशि, यदि कोई है, ड्यूटी का भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा दी जाएगी तथा इस ड्यूटी के भुगतान पर समाहर्ता अपनी मोहर तथा हस्ताक्षर से विलेख पर उक्त भुगतान का प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करेगा ।

(4) उप-धारा (2) उप-धारा (3) के अर्न्तगत समाहर्ता के आदेश से संतप्त कोई व्यक्ति जिस जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हस्तारित संपत्ति स्थित है उसमें अपील कर सकता है ।

(5) उप-धारा (4) के अधीन जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जानी है उसके प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जाएगी ।

(6) जिला न्यायालय इस अधिनियम के अधीन निर्धारित नियमावली में उल्लिखित रूप में अपील की सुनवाई तथा निपटान करेगी ।

**स्पष्टीकरण :-** इस अधिनियम की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य, उस मूल्य के अनुसार अनुमानित किया जाएगा, जो समाहर्ता या अपीलीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के अभिमत से ऐसी सम्पत्ति से उतनी राशि प्राप्त हो चुकी होगी या होगी, यदि यह हस्तांतरण पत्र, लेन-देन पत्र, उपहार पत्र, विभाजन पत्र, समझौता पत्र, की निष्पादन तिथि को खुले बाजार में बेची जाएगी ।

निरसन एवं बचाव

4. 1. भारतीय मुद्रांक ( दिल्ली द्वितीय संशोधन ) अध्यादेश, 2001 (2001 का 1) एतद्वारा निरस्त किया जाता है ।

2. ऐसी अपील में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई कार्य या कोई की गई कार्यवाही उसे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया या लिया गया समझा जाएगा ।



॥एस०आर०महेश्वरी॥

अवर सचिव ॥विधि एवं न्याय॥

एस०आर० महेश्वरी  
अवर सचिव (विधि एवं न्याय)  
दिल्ली सरकार  
(विधि एवं न्याय विभाग)  
नई दिल्ली.